



2026:AHC:64798

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 9571 वर्ष 2026

आशुतोष कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : आनंद गंगवार, कु. आस्था

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता(जी.ए.)

न्यायालय सं. - 67

माननीय अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति

1. श्री आनंद गंगवार, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री हिमांशु कुमार, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.) को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यह वर्तमान जमानत आवेदन अपराध संख्या 241 वर्ष 2025, बीएनएस की धाराओं 307, 331(4), 317(2), 103(1), थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद में विचारण की लंबितता के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं था जो मृतका के उस पुत्र द्वारा दर्ज कराई गई थी जो प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। तत्पश्चात् सह-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त राज कुमार, जिनका नाम भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था, को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके कबूलनामे में आवेदक का नाम उभरा। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक से कोई अपराधपरक सामग्री बरामद नहीं हुई और घायल के साथ-साथ मृत्यु से पूर्व मृतका ने भी बयान दिया था कि तीन व्यक्तियों ने उनके घर में घुसकर चोरी रोकने के प्रयास के दौरान उन पर हमला किया, यद्यपि वे उन्हें पहचान नहीं सके। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है और सह-अभियुक्त राज कुमार को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. 5363 वर्ष 2026 में दिनांक 13.02.2026 को पारित आदेश द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। इसलिए, समता के आधार पर आवेदक भी जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ने साथ दाखिल शपथपत्र में दो मामलों के आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, अतः अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और दिनांक 25.05.2025 से जेल में बंद है। उसे जमानत देने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.) ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया किंतु उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों पर विचार करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और अधिभारित जेलों तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए तथा **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **आशुतोष कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो जमानतदारों के साथ व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को तथ्य बताने से हतोत्साहित करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(ii) आवेदक कोई स्थगन मांगे बिना विचारण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में लिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

8. आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाएँ।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित की गई हो कि 15 दिन के भीतर प्रमाणित प्रति दाखिल की जाएगी।

10. विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जमानत नीति रणनीति, संदर्भ में: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) सं. 4 वर्ष 2021, दिनांक 31.01.2023 के आदेश,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(2024) 10 एससीसी 685 के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक को भेजे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

मार्च 28, 2026

एस.सी.

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।